starting the Short-Duration Discussion moved by Shri S. Jaipal Reddy.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, what happened to the Special Mentions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Members say that we will have it after the Short-Duration Discussion.

SHRIMATI KAMLA SINHA: No, Madam. Let us finish the Special Mentions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now you decide with your party people.

SHRIMATI KAMLA SINHA: This is not a party matter, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us agree. Let us have the Short-Duration Discussion regarding the GATT Treaty as moved by Shri Jaipal Reddy. I call upon Mr. Jaipal Reddy. Sorry, Mr. Malhotra, are you moving? I thought it was Mr. Jaipal Reddy. आप कहां जा रहे है ?

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : वह आगे आना चाहते हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We allow the people to come to the front benches when there are no mikes. If you have a proper mike, you can speak from your own seat. It is your dignity to speak from your own seat. If you are not heard, then I will allow you to come to the front benches.

SHORT DURATION DISCUSSION

Formulation of our Country's Final Decision on the GATT Treaty

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : उपसभापति महोदया, मैं एकऐसे प्रश्न पर विचार के लिए, बहस के लिए प्रस्तुत हुआ है, जो इस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । यह हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है । यह प्रश्न तय करेगा कि हमारे देश की प्रभुसत्ता रहेगी या नहीं, यह प्रश्न यह तय करेगा कि हमारी स्वतंत्रता कायम रहेगी या हम विदेशी इशारों पर नाचने वाले गुलाम बन करके रह जाएंगे । उपसभापति महोदया, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि 35 दिन के बाद हमारी सरकार अपनी इस बरबादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रही है । मैं इस प्रश्न को यहां रखना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को प्रारम्भ करते हुए यह कहा था कि :

"लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा भुगती"

उपसभापति महोदया, यह लम्हे कौन से थे, यह गलती कौन सी थी, यह गलती किन लोगों ने की यह जरूर उनको बताना चाहिए था कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़े गर्व से यहां पर कहा कि हमने 7 मेगा पॉवर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है । उन्होंने कहा कि यह एक एतिहासिक बात है कि हमने अरबों और खरबों रुपए की विदेशी कम्पनियों को हिन्दुस्तान में आने के लिए वहां पर तैयार किया है । परन्तु जब पॉवर प्रोजेक्टों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तब भी इसी प्रकार तालियां बजाई गई थी जैसा कि कल कांग्रेस के सदस्यों ने यहां पर तालियां बजाई । जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब यहां पर तालियां बजाकर और सारे देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बहुत जोर से आवाज उठाई गई और जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उस समय विरोध कर रहे थे उनको गालियां दी गई, उनको देशद्रोह तक कहा गया । उनसे कहा गया कि यह शोषण करने वाले हैं । जब यहां बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव आया तब भी उसका बड़े जोर से स्वागत किया गया । उपसभापति महोदया, इसी तरह से इंश्योरेंस को प्राईवेटाईजेशन करने की मल्होत्रा कमेटी की जो सिफारिशें हैं, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि तीन महीने

के अंदर-अंदर उसे लागू कर देंगे और यह कहा कि यह हमारी उदारीकरण की नीति का परिणाम है और इससे देश को बड़ा लाभ होगा । परन्तु जब इंश्योरेंस का राष्ट्रीकरण किया गया था तब भी उसके बारे में इसी तरह की बात की गई थी । जो लोग उदारीकरण की वाह-वाही लूटना चाहते हैं, यश लेना चाहते हैं उनको मैं जरा 1956 पर वापिस ले जाना चाहता हूं । 1956 में जब जवाहर लाल नेहरू जी ने हिन्दुस्तान की उद्योग नीति की घोषणा की थी, तो उन्होंने कहा था:

"The adoption of a socialist pattern of society as a national objective as well as the need for planned and rapid development require that all industries of basic and strategic importance or in the nature of public utility services should be in the public sector. Other industries which are essential and require investment on a scale have also to be in the public sector. The State has, therefore, to assume direct responsibility for the future development of industry over a wide area."

1948 में, 1956 और 1971 में जब राष्ट्रीयकरण का दौर चल रहा था, उस दौर में हिन्दुस्तान में वह लम्हे थे जिसमें हमने गलती की, जिसकी सजा इस देश ने 30–40 वर्षों तक भुगती । नेहरूवियन माडल को जो हिन्दुस्तान ने नेहरू जी के द्वारा लाया गया जिसमें कम्यूनिस्ट आइडियोलोजी को लेकर आये, केन्द्रीयकरण की व्यवस्था को लेकर आये, नौकरशाही के चंगुल में सारे देश को डाल दिया, यहां पर कंट्रोल्स लागू कर दिया । वे लम्हे थे जिसमें गलती की थी जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं । आपने अच्छा किया कि आज आपने नेहरूवियन माडल को दफन कर दिया, आज आपने उसे खत्म कर दिया, आज आपने नेहरूवियन माडल को पूरी तरह से नकार दिया । यह बात तो आपने ठीक की । यह बात तो आपने ठीक की परन्तु अब आप दूसरी गलती करने जा रहे हैं । आप ऐसी गलती करने जा रहे हैं कि उस केन्द्रीय करण के मुकाबले में, उस स्टेट कैपिटलिज्म के बदले में आप आज प्राइवेट कैपिटलिज्म, विदेशी कम्पनियों का पूंजीवाद, शोषक पूंजीवाद को कबूलने जा रहे हैं । एक गलती के बाद यह दूसरी गलती की जाने वाली है यह हमारे देश के लिये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लिबरलाईजेशन और ग्लोबलाईजेशन का जो अंतर है, उसको भी इस देश को समझना चाहिये । लिबरलाईजेशन में हम लोगों के हाथ में था कि हम अपनी गलतियों से बाहर निकल सकते थे । हमने 40 साल के बाद ही सही, अपनी गलती को सुधार लिया और उस गलती को सुधार कर हम उसमें से बाहर निकल आयें परन्तु ये जो ग्लोबलाईजेशन हो रहा है, यह जो डंकल संधि हो रही है, यह जो "गैट" की संधि है, इससे बाहर निकलना असंभव है । इसमें आप अंदर प्रवेश तो कर सकते हैं, इसके मेंबर तो बन सकते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर तो कर सकते हैं लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल सकते । यह एक ऐसी गुफा है जिसके अन्दर जाया जा सकता है परन्तु बाहर नहीं निकला जा सकता ।

उपसभापति महोदया, वित्त मंत्री को सबसे पहले यहां पर साफ तौर पर यह कहना चाहिये था और देश के सामने पहले माफी मांगनी चाहिये थी कि हम ने जो देश के साथ पहले गलती की थी उसके लिये हम शर्मिंदा हैं और हम ने उसका निराकरण कर लिया है परन्तु यह जो दूसरी गलती आप करने जा रहे हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पायेंगे करीब 30–40 साल के बाद जब आप की बरबादी के आसार सामने नजर आ जायेंगे, जब देश आर्थिक दृष्टि से गुलाम हो चुका होगा आर्थिक गुलामी अकेले नहीं आती है, आर्थिक गुलामी के बाद राजनीतिक गुलामी भी आती है तो उस राजनीतिक गुलामी और आर्थिक गुलामी में से आप बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है ।

इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो अगली गलती है, उसके

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

नुक्सान को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिये । मैं पहले ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम आधुनिकता के खिलाफ नहीं है। उच्च तकनीक हिन्दुस्तान में आये, हम इसके खिलाफ नहीं हैं । कोई व्यक्ति, कोई विदेशी कम्पनी हिन्दुस्तान में उच्च तकनीक लेकर आये, हिन्दुस्तान में कोई विज्ञान की बात आये, उसके लिये हमारा कोई विरोध नहीं है । अगर कोई ऐसी कम्पनी हिन्दुस्तान में आती है और वह यहां पर आकर के ऐसी उच्च तकनीक से पावर प्रोजेक्टस लगाये, डीपसी-फिशिंग का काम करें या तेल को खोजने का काम करें, इस तरह की कोई चीज वह करती है तो इस में कोई कठिनाई नहीं हो सकती जो परन्तु विदेशी कम्पनियां आ रही है, वह यहां केवल उच्च तकनीक लेकर नहीं आ रही हैं । ये कम्पनियां जो हिन्दुस्तान में आ रही हैं और जो "गैट" समझौते के अन्तर्गत आयेंगी, डंकल प्रपोजल से आयेंगी, ये कम्पनियां हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे उद्योग-धंधों में, काटेज इंडस्ट्रीज में, स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज में, यहां तक कि हिन्दुतान की आम खाने-पीने की चीजों में, उपभोक्ता वस्तुओं में आ रही है और यहां पर आने के बाद उसका क्या असर पड़ेगा, इस बात को हमें अच्छी तरह से जरूर समझना चाहिये ।

उपसभापति महोदया, कल यहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और यह कि डंकल प्रपोजल हमारे बड़े लाभ में है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me correct it. There is no Dunkel proposal as such. It is a Dunkel Draft. Dunkel is the name of the person who wrote the Draft.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): Draft is a proposal.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Proposal was by a committee which is known as GATT Proposal.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): The fact of the matter is that Dunkel is no longer there now.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उस की जगह पर दूसरा आदमी आ गया है पर "डंकल" नाम चिपका हुआ है और "डंकल" इसलिये इसमें चिपका हुआ है कि वह विकासशील देशों की गुलामी का दस्तावेज बनाकर चला गया । आप उस को प्रपोजल कहिये, ड्राफ्ट, कहिये, अब तो यह जो "गैट" संधि है, जिस पर हम हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, कल प्रधान मंत्री ने कहा यहां पर और कांग्रेस के लोग देश भर में इसकी कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस का कोई नुकसान नहीं है, यह देश में कोई लाभकारक चीज हो रही है, इस का बड़ा लाभ होगा परन्तु आपने जो यहां पर बजट पेश किया है, यह उस "गैट" की छाया में पेश किया गया है, यह जो डंकल संधि है, उसकी छाया में पेश किया गया । उसके अन्दर आप देखें, उसका एक मामला यह है कि यहां पर सबसिडी चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री में हो या सबसिडी खेती में हो, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो, सबसिडी धीरे धीरे कम कर दी जायेगी । यह उसी की गुलामी का असर है कि यहां पर हमारे वित्त मंत्री ने इस साल का जो बजट पेश किया है, उसमें सबसिडी कैसे कम की जाय, इस बात का ध्यान रखा है । आप बजट में देखिये, फूड, फर्टिलाइजर, एक्सपोर्ट प्रमोशन में 1993–94 में 10,300 करोड़ रुपये की सबसिडी थी, उस को कम करके 1994–95 में 8300 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यहां पर जो इंटरेस्ट एंड अदरस पर सबसिडी थी उसको 1600 करोड़ रुपये से कम करके 822 करोड़ कर दिया है । डेट रिलीफ जो फार्मर्स का 500 करोड़ रुपये का था वह 341 करोड़ कर दिया गया है । पोस्टल सबसिडी जो 173 करोड़ की थी उस को कम करके 125 करोड़ कर दिया गया है । करीबन 2045 करोड़ की सबसिडी कम कर दी गई है और यह कहा गया है कि किसानों के खिलाफ

इसमें कुछ नहीं है । लोगों को थोथा आश्वासन दिया गया है । गैट संधि के अन्तर्गत अभी से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके लिये रास्ता शुरू कर दिया है । 3000 करोड़ रुपये की सबसिडी कम कर दी गई है और कस्टम ड्यूटी में 2981 करोड़ की छूट दे दी है । महोदया, 28 परसेंट हमारे देश की जो आमदनी है वह कस्टम ड्यूटी से आती है और कस्टम्स ड्यूटी इसलिये कम कर दी गई कि गैट में माना गया है कि हम 25 प्रतिशत पर इस को ले आयेंगे । अभी से कस्टम्स ड्यूटी को हम कम कर रहे हैं ताकि विदेशों से आने वाला माल हिन्दुस्तान में कम कीमत पर आये और हिन्दुस्तान के अन्दर आकर कम कीमत पर बिके और हिन्दुस्तान के 90 करोड़ लोगों का बाजार विदेशी कम्पनियों के लिये खुल जाये । इसलिये कस्टम्स ड्यूटी में 2981 करोड़ रुपये कम कर दिये गये हैं । आप कह रहे हैं कि इसके ऐडवर्स ऐफैक्ट्स नहीं होंगे । क्या यह उस समझौते के नुक्सान की शुरुआत नहीं है जिसको हम मानने जा रहे हैं ?

उपसभापति महोदया, सबसे ज्यादा खतरनाक बात इसमें जो कही गई है, जिसका बजट के अन्दर रिफ्लैक्शन आया है, मैं चाहता हूं कि उसको भी यह सदन जरूर देखे । वह यह है कि ऐक्साइज ड्यूटी में बड़े बड़े उद्योगों को छूट दी है । 2000 करोड़ रुपये की ऐक्साइज ड्यूटी बड़े-बड़े उद्योगों में कम की गई है लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उन पर 2106 करोड़ रुपये की नई ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी है । 2106 करोड़ रुपये की नई ऐक्साइज ड्यूटी कुटीर व छोटे उद्योगों पर लगा दी गई है । इस नई ऐक्साइज ड्यूटी को लगा देने से इस का असर छोटे उद्योगों पर क्या पड़ा है, इसको भी आप देखिये । यहां पर 125 रुपये से नीचे बनने वाले जूतों पर कोई ऐक्साईज नहीं थी, अब उन पर भी ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी गई हैं । वहां पर गलीचे बनाने वाले, धागा बनाने वाले जो लोग हैं उन पर 15 प्रतिशत का ऐक्साइज लगा दी गई हैं । आयुर्वेदिक दवाओं पर 10 प्रतिशत की ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है । सूती धागे पर पहली बार ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है । पीतल की शीट बनाने वाले, स्टील की पत्तियां बनाने वाले छोटे-छोटे उद्योगों पर ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है । महोदया, यह ऐक्साइज ड्यूटी इसलिये लगाई गई है कि हमारे ऊपर उस गैट संधि का असर था । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके क्या बुरे प्रभाव होंगे, यह मैं आपको बताऊं इसके पहले ही वित्त मंत्री ने उसकी छाया बनने वाले बजट में ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी । आज देश में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुये हैं । हजारों इकाइयां बन्द हो गई हैं । मेरे पास अखबारों की कटिंग्ज हैं जिनमें यह बताया गया है कि मुरादाबाद में पीतल की शीट बनाने वालों और धागा बनाने वाले बुनकरों ने हड़ताल कर रखी है । शीट बनाने वाले, आयुर्वेदिक, दवाइयां बनाने वाले अपने कारोबार" से बाहर आ रहे हैं और यह स्थिति इसलिये पैदा हुई क्योंकि हमने जो डंकल ड्राफ्ट को माना है यह बात उसके अन्दर से आई है । आप देखें डंकल ड्राफ्ट क्या कहता है । वह कहता है :

Foreign investors to be treated at par with domestic companies in every respect; no restriction on foreign equity participation; no restriction on areas of investment; no restriction on use locally available products; free import of raw materials, components and intermediates; no export obligatoin to fund imports; eliminaiotn of investment policies that are against GATT provisions within two years.

हमारे वित्त मंत्री जी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये पहली बार इन चीजों पर एक्साइज लगाई है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है । मैं यह कहना चाहता हूं डंकल के जो प्रोविजन हैं जब उसको स्वीकार कर लिया जायेगा, जब गैट संधि पर हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे तो हिन्दुस्तान की जो स्माल स्केल और कोटेज इंडस्ट्रीज है वह कैसे बर्बाद हो जायेंगी, इस

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि जो स्थिति जर्मनी में है, जो स्थिति जापान में है, जो स्थिति दूसरे यूरोपीय देशों में है उसका मुकाबला करने के लिये वैसी परिस्थितियों का यहां पर निर्माण किया जाये । वित्त मंत्री जी की नीति इसी के अनुसार यह है कि बड़ी इंडस्ट्रीज और छोटी इंडस्ट्रीज में कोई अन्तर न रखा जाय । और छोटी इंडस्ट्रीज को भी उसके मुकाबले में कम्पीट करना चाहिये । क्या आप समझते हैं छोटी इंडस्ट्रीज, कोटेज इंडस्ट्रीज कम्पीट कर सकती हैं मल्टी नेशनल कम्पनीज के साथ ? 500 मल्टी नेशनल कम्पनियों के हाथ में दुनिया की 80 परसेंट ट्रेड है तो कैसे मल्टी नेशनल के मुकाबले आप एक छोटी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं ? क्या वह छोटी इंडस्ट्रीज उसका मुकाबला कर सकती है ? इसके मुकाबले बाजार ढूंढ सकती हैं ? अगर कोई ऐसा सोचता है, तो मूर्खता के स्वर्ग में रहता है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज देश की जो स्थिति है उसमें तकरीबन 10 करोड़ से अधिक लोग इस देश में बेकार हैं। इसमें से साढ़े तीन करोड़ के नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज हैं । साढ़े तीन करोड़ लोग जो रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज कराये बैठे हैं उन्हें कैसे काम दिलाया जा सकता है ? हमारे पब्लिक सेक्टर में 1979 के बाद एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली क्योंकि सरकार ने नौकरियों पर प्रतिबंध लगा रखा है । सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं और दूसरी तरफ गोल्डन हैंड शेक कर छंटनी कर रही है । सरकार धीरे-धीरे अपने एंपलाइज को निकालना चाहती है । बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के अन्दर और दूसरी इंडस्ट्रीज के अन्दर लाखों आदमियों की प्रतिवर्ष छंटनी हो रही है । इसके ऊपर अगर लेबल प्रोविजन को मान लिया गया, उसमें स्माल स्केल इंडस्ट्री भी आ गई, कंज्यूमर इंडस्ट्री भी आ गई, कोटेज इंडस्ट्री भी आ गई और सरकार ने उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी तो करोड़ों लोग और बेकार हो जायेंगे, क्या इसका आपने हिसाब लगाया? इस समय हमारे यहां कुल मिलाकर 3 करोड़ दस लाख लोग हैं जो स्माल सेक्टर इंडस्ट्री में, कोटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं । ये 3 करोड़ 10 लाख लोग जो स्माल स्केल इंडस्ट्री में और कोटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके मुकाबले में केवल 70 लाख लोग हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर एम्पलाएड हैं, सरकारी नौकरियों के अन्दर डेढ़ करोड़ लोग हैं । अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो 70 परसेंट के करीब जो एम्पलायमेंट है हिन्दुस्तान में वह छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग देते हैं । अगर पूरा मिला कर देखें तो भारत का अपना परम्परागत सेक्टर है उसमें से 70-80 परसेंट एक्सपोर्ट होती है । 50 परसेंट से ज्यादा एम्पलायमेंट ये प्रोवाइड करते हैं । ये तीन करोड़ दस लाख लोग बेकार हो जायें क्या आप यह चाहते हैं ? गैट प्रोविजन के मानते ही तीन करोड़ दस लाख लोगों के बेकार हो जाने का खतरा है । उसके बाद न सरकारी नौकरियों में जगह होगी, न पब्लिक सेक्टर में जगह होगी । ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां, मल्टी नेशनल कम्पनियां हिन्दुस्तान के अन्दर आटोमेटिक मशीन लायेंगी । हिन्दुस्तान के अन्दर रोबोटिज्म लायेंगी अगर यहां पर इम्पलाईमेंट काफी हद तक नष्ट हो जायेगा तो इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है ? अभी वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री ने कभी इस बात का निराकरण करने की कोशिश नहीं की, प्रणव मुखर्जी ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है और यह कहा कि मैं मानता हूं कि इससे इम्पलाईमेंट पर असर पड़ेगा, इम्पलाईमेंट कम हो जायेगा । अगर इम्पलाईमेंट कम हो जायेगा और हिन्दुस्तान में बेरोजगारी बढ़ जायेगी तो क्या यह अकेला मामला ऐसा नहीं है, क्या यह अकेला कारण ऐसा नहीं है—अगर तीन करोड़ दस लाख बेकार हो जायेंगे और दस करोड़ लोग पहले ही हिन्दुस्तान म

बेकार है – तो क्या यह कारण नहीं है कि इस समझौते को नकार दिया जाय या इस पर हस्ताक्षर न किये जाये। यहां यह भी कहा जाता है कि जो जर्मनी की स्थिति है, उससे हमें कंपीट करना है। हिन्दुस्तान में हमें उसी तरह के हालात पैदा करन पड़ेंगे। लेकिन जर्मनी और हिन्दुस्तान में फर्क है, जापान और हिन्दुस्तान में फर्क है, अमेरिका और हिन्तुस्तान में फर्क है। फर्क यह है कि जर्मनी की आबादी पिछले 40 सालों में लगातार कम होती जा रही है, अमेरिका की आबादी कम हो रही है। यूरोप के सारे देश, जी–7 के देश जो हैं उनकी आबादी कम होती जा रही है, वहां पर आबादी कम हो रही है, वहां पर लोग कम हैं और काम ज्यादा है। जब काम ज्यादा होता है और लोग कम होते हैं तो उसके लिए आटोमेटिक मशीनें लगाते हैं। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां वहां पर रोबोटिज्म चलाती हैं। परन्तु हमारे यहां आबादी तीन, सवा तीन प्रतिशत बढ़ रही है। यहां पर 10 करोड़ लोग पहले ही बेकार हैं तो आप जर्मनी का तरीका हिन्तुस्तान में कैसे लगा सकते हैं। अगर आप जर्मनी का तरीका चलायेंगे, यहां पर उसी तरह की हालत पैदा करना चाहेंगे तो हिन्दुस्तान का अपना चरित्र, हिन्दुस्तान की अपनी परम्परायें, हिन्दुस्तान की अपनी प्रकृति, हिन्दुस्तान की अपनी संस्कृति को समाप्त करेंगे ही, उसके साथ-साथ हिन्दुस्तान एक तरह से विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम बन जायेगा, इस सारे संकट को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप इस बात को समझें कि आप जो कह रहे हैं यह इतना आसान नहीं है। इन विदेशी कम्पनियों का मकड़जाल, इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का जंजाल कैसे फैलता है, किस तरह से वे हावी हो जाते हैं इसको समझने की कोशिश करें। क्या आप लोग उनको रेगुलेट कर लेंगे? रेगुलेट नहीं कर सकते। एक बार अगर ये विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान में आ गईं तो उनको फिर वापस नहीं भेज सकते हैं, इस समझौते के अन्तर्गत। पहले एक बार कोका कोला को निकाल दिया था लेकिन अब फिर कोकाकोला आ गया। कोका कोला कल्चर कैसा है आप इसको देखें। सी०पी०एम० पार्टी, बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने सारे हिन्दुस्तान में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ जेहाद खड़ा कर रखा है, वह अपने दैनिक पत्र में कोका कोला के इश्तहार छापती है। वह कोका कोला का इश्तहार छापकर, कोका कोला के एडवर्टिजमेंट को वह पूरी तरह से फ्लैश करती है और इसके बारे में यह जस्टिफिकेशन दिया जाता है यह हमारी मजबूरी है, यह कमर्शियल मामला है। हमें उससे पैसे लेकर उसके इश्तहार छापने पड़ते हैं। अगर कोका कोला के खिलाफ जेहाद खड़े करने वालों के दैनिक पत्र के अन्दर उनका इश्तहार छपे, उनको उसको छापने पर मजबूर होना पड़े, तो इस देश के अन्दर किस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सरकार को खरीद सकती है या पार्टियों को खरीद सकती है, यहां पर वह किस तरह से अपना पूरा का पूरा जंजाल पैदा कर सकती हैं, इस खतरे को हमें समझना चाहिये। महोदय, यहां पर चीन का उदाहरण दिया जाता है। मैं चार बार चीन गया हूं। चीन में पूरी तरह से सरकारीकरण है लेकिन वहां भी सबसे पहले कोका कोला आया। चीन के अन्दर भी कोका कोला पूरी तरह से चल गया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वहां भी फैल रही हैं। इसलिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का यह जो खतरा है इससे देश पर असर पड़ता है। अगर टाटा पर इसका असर पड़ता है, बिरला पर इसका असर पड़ता है, विदेशी पूंजीवादियों के स्थान पर हिन्दुस्तानी पूंजीवादी आ जायें, ऐसा हमारा ध्येय नहीं है लेकिन क्या इनमे हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्री पर असर नहीं पड़ेगा? इस खतरे को हम लोग नहीं भांप रहे हैं। इसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिये।

महोदया, मैंने जैसे पहले कहा आपने नेहरू माडल पहले ही दफन कर दिया है और आज गांधी जी की विचार धारा को भी

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

दफन कर रहे हैं। आप गांधी जी के ग्राम स्वराज को दफन कर रहे हैं। आप गांधी जी की बनायी हुई स्वदेशी की जो भावना है उसको समाप्त कर रहे है। आप यहां पर गांधी जी की चाहे मूर्ति लगायें या जार्ज पंचम की जगह पर गांधी जी की मूर्ति लगायें लेकिन आपने जो गांधी जी की विचारधारा थी, अर्थ-व्यवस्था थी, गांधी जी की भारतीयता और स्वदेशीपन की जो विचारधारा थी, उसको आपने पूरी तरह से नकार दिया है, उसको दफन करने जा रहे है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यह देखें कि क्या स्थिति पैदा हुई और किस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। पांच हजार रुपये का जूता बाहर से आए तो उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी, पांच हजार रुपये का अगर विदेशी जूता आता है तो कस्टम ड्यूटी कम कर दी लेकिन 10 रुपये की चप्पल बनाने वाले के ऊपर एक्साइज ड्यूटी में आपने बढ़ोत्तरी कर दी है। विदेशी शराब के ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है तथा पानी और दूध लोगों को महंगा बेचा जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कास्मेटिक्स पर एक्साइज भी कम कर दी और कस्टम भी कम कर दी, एयर कंडीशनर्स पर ड्यूटी कम कर दी, मोटर कार पर ड्यूटी कम कर दी है। यहां पर बेसिक ड्यूटीज एय्याशी की चीजों पर कम करते जा रहे हैं और उसकी जगह पर गेहूं के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, चावल के दाम बढ़ा रहे हैं, राशन के अन्दर दी जाने वाली चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं। उनके दाम बढ़ा कर गरीबों का खून चूस कर के हम यहां ग्लोबलाइजेशन करने जा रहे है। आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है। 117 देश इसमें शामिल हैं। इसलिए हम इसमे शामिल हो गये और इससे एक विश्व समाज बनेगा। हम उस विश्व समाज के अन्दर पूरी तरह से अपने आप को डालना चाहते है। उसमें आपने कहा कि बेरियर्स तोड़ दो, ड्यूटीज कम कर दो, सब रास्ते खोल दो, सभी जगह का माल एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरु हो जाए परन्तु क्या आपने इस बात को देखा कि विदेशों के पास जो माल है, अमरीका के पास जो उत्पादन है, वह हिन्दुस्तान की मार्किट चाहता है, 90 करोड़ की मार्किट चाहता है, इसलिए वह दरवाजे खुलवाना चाहता है, दबाव डाल रहा है। परन्तु जो हिन्दुस्तान के पास चीज है, मैन पावर है, उस मैनपावर के लिए वह अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलता है। अमरीका ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, इंग्लैंड ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, जर्मनी और जापान तथा जी-7 के देश ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे हिन्दुस्तान के कारीगरों के लिए क्यों बन्द कर रखे हैं? जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कारीगरों के लिए, प्लम्बरों के लिए, हिन्दुस्तान के कारपेंटर्ज के लिए, हिन्दुस्तान के डाक्टरों के लिए, हिन्दुस्तान के कम्प्यूटर साइंटिस्टस् के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोले जाते है? ग्लोबलाइजेशन करो तो पूरी तरह से करो। अगर हमारे यहां विदेशी ताकतें आना चाहती हैं तो वह हिन्दुस्तान की मैनपावर के लिए अपने दरवाजे क्यों बन्द करते हैं? उनके इम्मीग्रेशन रूल्ज को आप देखिए इतने अमानवीय, इतने इन्सानियत से गिरे हुए रूल बना रखे है। अगर कोई वहां पर चला जाए तो उसकी पत्नी आ नहीं सकती। उसका विवाह हो जाए तो पत्नी को निकाल दिया जाता है, बच्चे वहां नहीं रह सकते। ऐसे कानून बनाते हैं। उसके ऊपर लोगों के लिए दरवाजे बन्द करते हैं, वहां पर पूरी तरह से इस पर रोक लगाते हैं। आपने उनसे यह सवाल क्यों नहीं उठाया? इससे पहले कि ग्लोबलाइजेशन की बात मानी जाए, इस प्रश्न को पूरी तरह से उनके सामने आपने क्यों नहीं रखा? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ग्लोबलाइजेशन है, यह एक प्रकार की धोखे की बात है। उसके अन्दर इस तरह की चीजें नहीं आना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां पर एक और बात की है। हालांकि उसका

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने की बात है। ब्रांड नेम्स के ऊपर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो छूट मिलती थी, वह बन्द की है। मैं ब्रांड नेम्स के खिलाफ हूं, विदेशी कम्पनियों के भी खिलाफ हूं। परन्तु अभी तक जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लाखों लोग सामान बेचते थे, आज उनसे वह सुविधा विदड्रा कर ली गई है। इससे वह स्माल इंडस्ट्रीज भी पूरी तरह से बन्द हो जाएंगी। उनके बन्द हो जाने के बाद यहां पर जो चीजें ब्रांड नेम पर बिकती थी या तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकले नहीं तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैंने कहा इससे जो इनका नुकसान है, मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस पर विचार करे। एक तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बात मैंने कही है। मैंने कहा कि मैनपावर को रोका गया है। परन्तु फिर यह प्रश्न पैदा होगा कि हमारे जो पहले से कानून हैं, इस देश का हमारा अपना कांस्टीट्यूशन है, यह सुप्रीम होगा या गैट की नियम सुप्रीम होंगे? अगर हमारे देश के नियमों से ऊपर, हमारे देश के कानून से ऊपर, हमारे देश के संविधान के ऊपर गैट के नियम होंगे, गैट की संधि होगी, गैट के नियम होंगे तो हमारी प्रभुसत्ता कहां पर है? कहां रहेगी हमारे देश की अस्मिता? कहां रहेगी हमारे देश के संविधान की सर्वोच्चता, अगर वह नियम लागू हो जाएंगे? इसलिए इस बात पर सदन को विचार करना चाहिए। यह प्रश्न कोई छोटा प्रश्न नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें और हैं, जो हमारे लिए नुकसान में जा रहीं हैं। एक तो यह जा रही है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पक्ष में है, उसका तो उलट दिया जा रहा है और हमारे जो खिलाफ है, तुरन्त लागू किया जा रहा है। पहली बात पेटेंट लाज के बारे में है। जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स हैं, ट्रिप्स, उनके लिये यह कहा जा रहा है कि 20 साल तक इनको रखा जाये 20 साल तक ट्रिप्स की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि 20 साल तक उनके इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स रहेंगे। कोई आदमी किसी चीज को पैदा करता है, कोई अविष्कार करता है, तो उस आविष्कार का लाभ उसको मिल जाये, इसमें कोई नकसा नहीं है। किन्तु कोई आविष्कार किस एक व्यक्ति ने आज किया है, तो उस पीछे दुनियां में मानव का करोड़ों वर्षों का अस्तित्व, हजारों वर्षों की सभ्यता का निचोड़ होता है और केवल एक व्यक्ति सारी दुनिया में उसका लाभ लेता रहे यह बात ठीक नहीं है। इसीलिए इसका क्या असर पड़ेगा, इसको भी हमें देखना चाहिए।

हिन्दुस्तान में हमारा पेटेंट एक्ट है, 1970 का, यह जब लागू हुआ तो उससे पहले हिन्दुस्तान में दवाइयां सारी दुनिया में सबसे महंगी थीं। परंतु 1970 का पेटेंट एक्ट लागू होने के बाद हिंदुस्तान में दवाइयां सारी दुनिया में सब से सस्ती है। यहां पर जो दवाइयां हैं, उनमें से मैं तीन चार का उदाहरण देना चाहता हूं, ज्यादा के उदाहरण आपके सामने नहीं रखता हूं, इसमें समय लग जायेगा। यहां पर रेनेटिडीन नाम की दवाई हिन्दुस्तान में 29 रु० में 10 गोलियों का पत्ता है, तो अमरीका में 744 रूपये का है। यहां पर डेक्लोफेनक 5.67 रुपये की है तो अमेरिका में 239 रूपये की, यहां पर विनक्रिस्टिन 28.80 रूपये की है, तो अमेरिका में 1068.37 रूपये की है। इस तरह से यह लम्बी लिस्ट है। अगर आप कहें, तो मैं सदन में रख सकता हूं, जिसमें कि दवाइयों की कीमतें 40.50, 100 गुना अमेरिका में हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जब देखा कि हिन्दुस्तान की दवाइयों ने उनकी मारकेट छीन ली है, उनकी मारकेट पर कब्जा कर लिया है, वे बाजार से बाहर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने इस समझौते के अन्दर 20 साल के लिये पेटेंट लाज अपने पास रखने के लिए इसमें तब्दीली करा दी। इससे पहले केवल यहां पर प्रोसेस पेटेंटिंग थी, परन्तु प्रोडेक्ट पैटेंटिंग नहीं थी। किसी प्रोसेस से और आप उत्पादन कर ले तो उसके ऊपर यह लागू नहीं था। अब प्रोसेस पेटेंटिंग के साथ-साथ प्रोडेक्ट पेटेंटिंग भी इसमें लागू कर दिया गया है और प्रोसेस पेटेंटिंग तथ प्रोडेक्ट पेटेंटिंग के बाद किसी दवाई का निर्माण

हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता, जिसकी पेटेंटिंग अमेरिका में हो गयी है। अमेरिका में पेटेंटिंग कराने के बाद पहले यह था कि तीन वर्ष में अगर आप कार्मशियलाइज नहीं करेंगे, तो आप उसका यहां पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब उसको भी हटा दिया गया। अब उसमें यह कहा गया है कि इम्पोर्ट बिल वी कंसोर्डड एज प्रोडक्शन यानी अगर कोई कम्पनी वहां बनी और वहां से इम्पोर्ट करके-हिन्दुस्तान में चीज को भेजे, तो भी आप उसका प्रोडक्शन यहां पर नहीं कर सकते। इस बात पर यहां कितनी दवाइयों की कीमतें 40, 50 या 100 गुना तक कैसे बढ़ जायेंगी, इसका अन्दाजा लगाना चाहिये।

श्रीमन्, यह कहना मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत है कि 10 परसेंट दवाइयों की कीमतें बढ़ेंगी – केवल 10 परसेंट मैं समझता हूं कि यह देश को भी धोखा देने की बात है। इस समय जो अमेरिका में दवाइयां पेटेंट हो चुकी हैं, उनमें, से एण्टी बायोटिक क्षेत्र में 42 परसेंट एण्टी बायोटिकरियल क्षेत्र में 98 परसेंट एण्टी लेप्रोटिक्स में 70 प्रतिशत, एण्टी अल्सर में 66 प्रतिशत, हृदय रोग की की 51 प्रतिशत और परिवार नियोजन के बहुत से क्षेत्रों में 87 प्रतिशत दवाइयां पेटेंट हुई हैं। जब इनकी कीमतें 30, 40, 50 गुना बढ़ जायेंगी, तो आप क्या किसी से कह सकते हैं कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है और दूसरे रोग की दवा सस्ती मिल रही है, तो उसको जाकर खरीद लो। हृदय रोग का कोई मरीज है, उसको दवाई चाहिये, उसकी कीमत सौ गुनी हो गयी, क्या आप उसे कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो, तो वह बहुत सस्ती बाजार में मिलती है। 10 परसेंट दवाइयों की कीमतों के बढ़ने की बात तो पहले ही गलत है, परन्तु जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जिनका ताल्लुक हृदय रोग से, कैन्सर से है, जिनका ताल्लुक अल्सर से है, जिनका ताल्लुक जिनका मैंने जिक्र किया है, उनसे है, उन दवाइयों की कीमतें, 30, 40 गुना बढ़ जायेंगी। हिन्दुस्तान में दवाइयां महंगी हो जायें और उसके ऊपर इस सरकार ने एक ओर काम कर रखा है। यह कहा है अस्पतालों से कि तुम्हें सबसिडी नहीं दी जायेगी। आई०एम०एफ० ने वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अस्पतालों की सबसिडी खत्म करो, सोशल सेक्टर समाप्त करो। अस्पतालों में आप दवाइयां दे नहीं, अस्पतालों में आप टैस्ट निशुल्क करें नहीं और गैट संधि पर हस्ताक्षर करके दवाइयों की कीमत आप 40 गुणा, 50 गुणा होने दें, तो क्या मरीज बिना दवाइयों से मर जायें? क्या गरीब आदमी को दवा उपलब्ध न हो। दवा की कीमत आप बढ़ा दें और इस तरह से हमारी देश के रोगी मरने पर मजबूर हो जायें और फिर भी आप कहें कि डंकल का बड़ा लाभ होगा, डंकल समझौता हिन्दुस्तान को बड़ा लाभ पहुंचायेंगा और उसमें जिक्र करें कि कुल मिला कर 2 बिलियन डालर अर्थात 6 हजार करोड़ रुपये का हमारा निर्यात क्योंकि उससे बढ़ जायेगा, इसलिये यह बड़े फायदे में होगा। इस तरह का धोखा देने की कोशिश क्यों की जाती है? श्रीमन् 6 हजार करोड़ रुपये का निर्यात बढ़ेगा, परन्तु जब 6 हजार से 10 हजार करोड़ की आप कस्टम ड्यूटीज कम कर देंगे..... **(व्यवधान)**..

(Time-bell rings). I will take just five, to seven minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You have already exceeded 33 minutes of the time allotted to your party.

SHRI VIJAY KUMAR MOLHOTRA: I am told we have 52 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please conclude.

प्रो०विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर दवाइयों के बारे में मैंने जिक्र किया कि कस्टम ड्यूटीज कम होने से

और इन सब चीजों के कम होने से किसमे कितना असर पड़ेगा और उससे भी ज्यादा रुपया हमसे निकल जायेगा । श्रीमन्, इसके बाद सवाल बीजों के बारे में आता है, किसानों के बारे में बार-बार इस बात का जिक्र किया गया है, कल प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि हम कानून बना देंगे और कानून बनाने से गैट के नियम हम पर लागू नहीं होगा । बीजों के बारे में, पौधों के बारे में, सीड्ज, प्लांटस एनीमल किंग्डम इन सब के बारे में जो गैट के उसमें प्रावधान हैं,उन प्रावधानों के मुताबिक आप बीजों का आदान-प्रदान नहीं कर सकते हैं । बीज अपने साथी को दे नहीं सकते हैं, उससे ले नहीं सकते हैं । बीज को बाजार में बेच नहीं सकते और अगर आप बीज का आदान-प्रदान नहीं कर सकते, जो हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है तो उसके बाद बीजों के आदान-प्रदान नहीं करने पर और उसकी स्थिति आने पर पौधों, बीज, एनीमल किंग्डम में हम विदेशी कंपनियों के हाथ में खिलवाड़ बन करके रह जाएंगे ? हमारे खेतों में, खलिहानों पर, हमारे जंगलों में, नदियों पर, हमारी वन संपदा पर वनस्पति पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा और हम क्या बोए, क्या खाएं क्या करें, इसके बारे में हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर होंगे ? यह कहना कि यह प्रावधान हम पर नहीं लागू होंगे क्योंकि हमारी अभी सबसिडी कम है तो यह क्या जब आप सबसिडी बढ़ा देंगे तो उसके बाद ये लागू नहीं होंगे । यह कहना कि हमारी कुल मिलाकर हमारी औसत प्रति व्यक्ति आय 300 डालर प्रति वर्ष है, एक हजार डालर प्रतिवर्ष जब हो जाएगी तब हमारे पर कुछ प्रावधान गैट के लागू होंगे, यह भी है क्या हमेशा हम 300 डालर प्रति व्यक्ति आय पर ही रहेंगे ? यह कहना कि हमारी फारेन एक्सचेंज की स्थिति, जो विदेशी भुगतान है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे विदेशी भुगतान की स्थिति खराब है । तो आपने तो स्वयं कहा है कि हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है अगर आप यह कहते हैं तो उसके बाद इनका असर नहीं पड़ेगा यह कहना बहुत ही गलत बात है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने "जागरण" अखबार में श्री प्रणव मुखर्जी का एक इन्टरव्यू पढ़ा । वह जागरण अखबार मेरे पास है । उन्होंने कहा कि यह मजबूरी है । हम क्या करें ? कोई आल्टरनेटिव नहीं है, कुछ बातें इसमें खराब हैं, पर हमारे लिए यह मजबूरी है । मजबूरी किस बात की है आज जो मजबूरी है, कल कैसे वह अभिशाप बन जाएगी इसकी कभी आपने कल्पना की है ? यह तो उसी तरह से है जैसे कोई महिला पहले तो अपना खर्चा बढ़ा ले, अय्याशी के साधन ला-ला करके अपना खर्चा इतना अधिक कर ले अपनी स्थिति ऐसी बना ले कि उसके ऊपर खर्च बेइंतहा हो जाए और बाद में कहे कि यह उसकी मजबूरी है कि अब देह बेचने के सिवाय और कोई चारा नहीं है । अब मुझे अपना जिस्म बेचने के अलावा कोई . . . . (**व्यवधान**)

श्री एस०एस० अहलुवालिया : (बिहार) सर, प्वायंट आफ् आर्डर । एक महिला के बारे में ऐसा कहना कि साहब, वह अय्याशी और यह देह बेचना, यह क्या है ? . . . (**व्यवधान**) नहीं आपको अगर कोई उदाहरण देनी है तो इसमें महिला क्यों ? महिला आपकी मां भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है । उसके बारे में आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : श्रीमान् जी, आपका तो काम है . . . . (**व्यवधान**)

श्री एस०एस० अहलुवालिया : नहीं, आपका यह उदाहरण गलत है । . . . . . (**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आपका काम है तालियां बजाना . . . . (**व्यवधान**)

श्री एस० एस० अहलुवालिया : किसी महिला के बारे में आपने कैसे कह दिया ? आपका उदाहरण गलत है । आप इसको स्वीकार करें । यह अपने नेता से पूछें कि यहां महिला का उदाहरण दे सकते हैं । . . . . (**व्यवधान**) आप महिला का उदाहरण दे रहे हैं । महिला आपकी मां भी है, बहन भी है और बेटी भी है । आप उसका

ऐसा उदाहरण मत दें। ....(**व्यवधान**) यह गलत बात है। ....(**व्यवधान**)

प्रो० जियव कुमार मल्होत्रा : मैं एक* की बात कर रहा हूं और यह * की तरह से हमारी सरकार ....(**व्यवधान**)

श्री एस०एस० अहलुवालिया : महिला की तुलना अगर आप * के साथ करना चाहते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारतमाता की तुलना एक* के साथ करना चाहें तो यह दुर्भाग्य की बात है। .... (**व्यवधान**) यह शर्म की बात है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : शर्म की बात है आपके लिए जिन्होंने देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।.... (**व्यवधान**)....

श्री एस०एस० अहलुवालिया : महोदय, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये भारत माता के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक महिला पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप गैट पर बोल रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जो बात कह रहा हूं ....(**व्यवधान**) ....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : अहलुवालिया जी, आप बैठिए।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : आप महिला पर आरोप लगा रहे हैं और ऊपर से * कहते हैं। ....(**व्यवधान**).... महोदय, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ ....(**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं बताता हूं आपको कि भारतीय संस्कृति क्या है। मैं यह कहना चाहता हूं उपसभाध्यक्ष महोदय कि एक सती स्त्री की तरह से ....(**व्यवधान**)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री एस०एस० अहलुवालिया : महोदय, ये अपने अल्फाज वापिस लें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : किस बात पर अल्फाज वापिस लें ?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : इन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है। ये * के बारे में बोल रहे हैं। ये गैट की तुलना भारत माता के साथ कर रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. D. SALIM): Mr. Ahluwalia, you have made your point. (*Interruptions*)

SHRI SOM PAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, Mr. Ahluwalia should not put words in his mouth.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is saying the same thing. You look into the record. (*Interruptions*)

SHRI SOM PAL: It is totally unbecoming of a Member of Parliament to behave like this. He cannot be allowed to *like that in your presence, Sir. Mr. Jagesh Desai, don't protect him. He has made his point which is enough. That is all. He has become habitual of all this (*Interruptions*)

श्री एस० एस० अहलुवालिया : आप * करते रहो और हम सुनते रहे ?

श्री सोम पाल : आपने आदत बना ली है।*

श्री एस० एस० अहलुवालिया : हां, आदत बना ली है।

श्री सोम पाल : आप अनर्गल प्रलाप करने के आदी हैं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैं आदी नहीं हूं। क्या आप * कह सकते हैं ?

श्री सोमपाल : नहीं कहा, किसी ने ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : यह मैं नहीं सुन सकता ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) आप बैठिए ।

SHRI SOM PAL: I cannot listen all this. (*Interruptions*) Mr. Vice-Chairman, you discipline him. Otherwise, you will not be able to run the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. D. SALIM): Nothing will go on record. (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: All this is very unfortunate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. D. SALIM): You have made your point Mr. Ahluwalia. I listened to your viewpoint. Now, please sit down.

SHRI SOM PAL: Sir, this has to be settled once and for all. (*Interruptions*) Mr. Desai, it has been well taken.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I never expected such type of comparisons from you

SHRI S. JAIPAL REDDY: My humble submission is that you look into that part of the record and decide.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही है, मैं फिर से बताता हूं । **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सोमपाल जी, आपके नेता बोल रहे हैं ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): It is not in good taste.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Vice-Chairman will look into it.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Why can't he himself withdraw that?

SHRI JAGESH DESAI: This kind of comparison is not in good taste.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं टेस्ट भी बताता हूं । . . . **(व्यवधान)** . . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : अहलुवालिया जी, मल्होत्रा जी का कहना है कि वह ऐसा कुछ नहीं कहे हैं जोकि आपके लिए गलत रुचि का हो ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदय, हम पर जो आरोप लगाया है उन्होंने, वह गलत है । उसका जो कम्पेरिजन किया है, वह गलत है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : अगर ऐसा कोई आरोप लगाया है, तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): श्रीमन् अगर कोई सदस्य बोल रहा है और किसी को आब्जेक्शन है तो वह बड़ी शांति से खड़े होकर कह सकता है कि यह गलत है, इसे देख लीजिये, लेकिन हमारे मित्र अहलुवालिया जी हमेशा डांटने लगते है जो बोल रहा है उसे यह कोई तरीका नहीं है । वे सज्जनता से खड़े होते और कहते हैं कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह आप कह सकते हैं, लेकिन यह क्या तरीका है ? आपकी आदत पड़ गयी है । श्रीमन, मैं विनती करूंगा कि आप आब्जेक्शन करें तो नम्रता से कीजिये, लेकिन डांट शाउट । आप कहते कि, विजय जी यह आपने कहा है, यह उचित नहीं लगता कृपया इसे वापिस ले लीजिये । यह कहने का कोई तरीका है आपका? आप शोर मचाने लगते हैं । बड़े फेफड़े दिये हैं भगवान ने तो उनको हमारे ऊपर तो नहीं डालिये ।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता

था कि इस देश को तैयार करें, इस देश को स्वाभिमान की तरह से तैयार करें, परन्तु कांग्रेस पार्टी देश के स्वाभिमान को खड़ा करने की बजाय उस*की तरह से अपनी मजबूरी जाहिर करना चाहती है जोकि अपना खर्चा बढ़ा लेती है एक अपनी मजबूरी जाहिर करना चाहती है, जो अपने खर्चे बढ़ा देती है । . . (**व्यवधान**)

श्री एस० एस अहलुवालिया : सर, फिर कहा इस देश को* यह क्या है? . (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, this is not in good taste

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, it is very objectionable. It cannot be tolerated. . . . (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It shows your misconduct.

SHRI JAGESH DESAI: It is objectionable.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मजबूरी की बात है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री एस० एस अहलुवालिया : मजबूरी की बात क्या करते हैं ?*

*शर्म करो । (**व्यवधान**) . .

SHRI V. NARAYANASAMY: Dont behave like this Don't make such allegations.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Is he a cultured man? Is it the word of a cultured man?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बात आपसे कह रहा हूं । (**व्यवधान**) उपसभाध्यक्ष जी,* शब्द बदल देता हूं । . . (**व्यवधान**) . .

श्री एस०एस अहलुवालिया : यह बी० जे०पी० की संस्कृति है । यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है । मैं मुरली मनोहर जोशी जी से एक सवाल करना चाहता हूं । . . . (**व्यवधान**) . . . जोशी जी से सवाल करता हूं, सिकन्दर बख्त साहब से सवाल करता हूं । . . (**व्यवधान**) . .

श्री सिकन्दर बख्त : उन्होंने वापस ले लिया । आप बैठिये ।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह सरकार पहले अपने खर्चे बढ़ा लेती है, सरकार पहले देश के अन्दर करोड़ों-अरबों रुपये का विदेशी कर्जा ले आती है, सरकार पहले तो अपने देश के अन्दर गरीबों का खून चूसकर के देश के 60 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे ले आती है और जब यह स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर कहती है कि हमारी मजबूरी है, अब हम क्या करें । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के स्वाभिमान को आप खड़ा करें और इनसे यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति इन्होंने पैदा की, वह ऐसी है, जैसे–

"तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही है,
यह राहें, तबाही के घर जा रही है ।"

यह राहें तबाही के रास्ते पर जा रही है । इस रास्ते पर मत पड़ो । कुरुक्षेत्र में जैसे श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था–

"क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ
नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ
परन्तप ।।"

मैं कहना चाहता हूं कि श्री नरसिंह राव जी, देश में जो हीनता है, दीनता है और मैं जो शब्द प्रयोग करूंगा, जो गीता का है, तो फिर इन्हें कठिनाई होगी,

*Expunged as ordered by the Chair

†[]Transliteration in Arabic Script.

उसमें कहा है कि इस नपुसंकता के रास्ते पर मत जाओ, यह आपको शोभा नही देता । खड़े हो, उठो, उतिष्ठित, इस देश के स्वाभिमान को पैदा करो, हमारी बर्बादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करो । यह लमहे जो है, जिनमें आप गलती करने जा रहे हैं, इसकी सजा अगली आने वाली सदियों तक इस देश को भुगतना पड़ेगी । इस देश को आर्थिक गुलामी और उससे अनिवार्य राजनैतिक गुलामी की ओर में मत ले जाओ । यह देश पूरी तरह से अपनी स्वाधीनता में रहे, जो हजारों लोगों ने अपने खून से बड़ी मुश्किल से एक हजार वर्ष बाद इसे पाया । इसके लिये कई हुतात्माओं ने अपना खून दिया, आप उनके खून पर पानी न फेरें, महात्मा गांधी की विचाराधारा को नष्ट न करें, देश की आजादी को नष्ट कर पराधीनता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें । जापान के प्रधानमंत्री की तरह से अमरीका की आंख में आंख मिलाकर, विदेशी ताकतों की आंख में आंख मिला कर उनसे कहें कि यह 90 करोड़ का भारत देश अब गुलाम नही होगा । आप इस पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार करके यहा पर आइये तब हम आपका स्वागत करेंगे और तब हम कहेंगे कि आपने ठीक कदम उठाया, नहीं तो जो आप करने जा रहे है, उसके लिये आपको आने वाली पीढ़िया धिक्कारती रहेंगी । हस्ताक्षर करते समय इसका आप विचार करें ।

श्री सोमपाल : उपसभाध्यक्ष जी, यह विषय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है । इसमें न केवल हमारे देश के हितों की बात अपितु सारे विकासशील देशों के हित की बात होनी है और इस बहस के दौरान उपस्थिति नगण्य है । मैं यह प्रस्तावित करना चाहता हूं कि कम से कम आधे घटे के भोजनावकाश की आप अनुमति दें, उसके उपरांत यह चर्चा शुरू की जाये । **(व्यवधान)**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is in the interest of the Members. You have demanded a debate and when the demand is accepted, you will not remain over here.

SHRI SOM PAL: We are not shirking the demand for a debate, Mr. Minister. Sir, through you, I want to tell him I am just looking for a better audience in the House. That is all. If the presence of the Members improves,... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGESH DESAI: We are audience! What do you mean by 'audience'?

SHRI SOM PAL: I am sorry, Mr. Desai. I am sorry, I used the word 'audience'. It should have been a better representation in the House., a better participation in the House. Therefore, I request that for half-an-a better participation in the House. hour we should rise for lunch. ... (*Interruptions*)...I immediately prompted (*Interruptions*) ...

SHRI V. NARAYANASAMY: It means you are not interested in the debate.

श्री सोमपाल : मैं सिर्फ इस उद्देश्य से कह रहा हूं ताकि ज्यादा सदस्य इसमें भाग ले सकें । और कोई दूसरी बात नही है । **(व्यवधान)**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You are a Member. After finishing your speech, even you will not be present in the House. That practice has also develop in the House.

SHRI V. NARAYANASAMY: It had happened. When the Minister replied, only some Members were present.

SHRI S. JAIPAL REDDY: If the ruling party Members and the Minister agree, I have no objection. I suggest that we should have a half-an-hour lunch session. Only half-an-hour.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have no objection to a lunch-break. I am saying that as a Member of this House we should be more responsible. When we demanded a debate, we should participate in that debate.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मुखर्जी बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम लोग जोथोड़े-बहुत बैठे है, सुनना चाहते है. . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): It was decided in the BAC meeting to skip the lunch hour.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Sir, I think the hopes and expectations of Mr. Som Pal are not grounded in reality. The fact is that in this House at every... (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: This proposal is absolutely innocuous. I don't know why they are discussing it. If the Minister has any objection, we are prepared to go ahead. That is the end of the matter.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have no objection to a lunch-break.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the Minister has no objection to a lunch-break.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Sir, I have a great objection to a lunch-break.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Sir, he is a very solid man But what about us?

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I will tell you why I am objecting to it. Sir, I have already taken my lunch.

SHRI SOM PAL: Sir, adjourn the House for half-an-hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I adjourn the House for half-an-hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri Md. Salim) in the Chair.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1993-94 (March, 1994)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Before we continue the discussion on the GATT Treaty, we will take up the Supplementary Demands for Grants (General) 1993-94 (March, 1994).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. ABRAR AHMED): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1993-94 (March, 1994).

SHORT DURATION DISCUSSION

On the formulation of our country's final decision on the GATT Treaty— *contd.*

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, may I place before the House a fact that as I anticipated the gentleman who has asked for the lunch hour with the idea of having a larger gathering in the House, a larger presence in the House hon. Member Som Pal is himself absent from the House after the lunch hour. I merely wish to point out... (*Interruptions*)...

SHRI M. A. BABY (Kerala): Sir, we should not refer to Members who are absent from the House.